Dainik Bhaskar (Indore), 16th July 2024, Page-05

आईआईटी में नर्मदा घाटी प्रबंधन केंद्र शुरू, 1000 किमी तट की मैपिंग होगी

अभियान को मूर्त रूप देने 3-डी मॉडल के रूप में प्रोटोटाइप भी बनाया गया

भास्कर संवाददाता | इंदौर

आईआईटी इंदौर में रविवार को 'जल शक्ति मंत्रालय' की 'नर्मदा घटी प्रबंधन' परियोजना के तहत नर्मदा घटी प्रबंधन अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्र द्वारा नर्मदा नदी के 1000 किमी के तट की मैपिंग की जाएगी। इसके लिए नर्मदा घाटी का 3-डी मॉडल के रूप में एक प्रोटोटाइप भी बनाया गया है। इससे घाटी की मैपिंग और पर्यावरण संरक्षण में विभिन्न चुनौतियों को दर्शाया जा सकेगा। इस मौके पर आलीराजपुर जिले के नर्मदा घाटी में सामुदायिक ईकोसिस्टम की पुनर्स्थापना, नर्मदा जीर्णोद्धार के लिए समाज के माध्यम से अभियान छेड़ने, नर्मदा घाटी में वन भूमि का महत्व, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनरुद्धार गतिविधियां व नर्मदा घाटी में पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर मंथन किया गया।

केंद्र का उद्घाटन डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. समीर वी कामत ने किया। आईआईटी इंदौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. के सिवन, आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रो. सुहास एस. जोशी, आईआईटी कानपुर के प्रो. विनोद तारे उपस्थित रहे।

नर्मदा नदी क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों, पेशेवरों व शिक्षाविद को साथ लाएंगे

- प्रो. जोशी ने कहा, हम नर्मदा नदी क्षेत्र से संबंधित ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों, पेशेवरों और शिक्षाविद को साथ लाएंगे। इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए एकीकृत प्रबंधन दृष्टिकोण और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है।
- डॉ. कामत ने नर्मदा घाटी के अध्ययन और मध्यप्रदेश राज्य में जल प्रबंधन के लिए ईकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रो. मनीष गोयल के नेतृत्व में आईआईटी इंदौर के फैकल्टी मेम्बर प्रो. प्रीति शर्मा, प्रो. किरण बाला और प्रो. मयूर जैन की टीम के प्रयासों की सराहना की।
- डॉ. सिवन ने इस परियोजना पर काम करने के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि इस तरह की योजनाएं पर्यावरण पुनरुद्धार के साथ नदी संबंधी कमर्शियल गतिविधियों के संदर्भ में समाज को सीधे तौर पर मदद करेंगी।
- 'नमामि गंगे' परियोजना की शुरुआत करने वाले प्रो. विनोद तारे ने एकीकृत नदी क्षेत्र प्रबंधन के महत्व और नर्मदा नदी की स्वच्छता को संरक्षित करने के लिए दीर्घकालिक पद्धतियों की आवश्यकता पर जोर डाला। उन्होंने नीतियां बनाने के लिए वैज्ञानिकों की मदद की आवश्यकता की बात कही।